विचार बिन्दु

विश्व में अग्रणी भूमिका निभाने की आकांक्षा रखने वाला कोई भी देश शुद्ध या दीर्घकालीन अनुसंधान की उपेक्षा नहीं कर सकता। -होमी भाभा

जीडीपी बेहतर मापने के लिये तरीकों में जरूरी बदलाव!

देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर ढंग से दिखाने के लिए केंद्र सरकार जीडीपी को मापने के तरीके में बड़े बदलाव कर रही है। बताया जा रहा है कि इन बदलावों का मकसद भारत के जीडीपी आंकड़ों को ज़्यादा सही, विस्तृत और असली अर्थव्यवस्था को दिखाने वाला बनाना है। भारत की अर्थव्यवस्था पहले कृषि-प्रधान थी, लेकिन अब सेवाक्षेत्र, आईटी, बैंकिंग, स्टार्टअप, डिजिटल सेवाएं आदि का योगदान बहुत बढ़ गया है। जब अर्थव्यवस्था में नई-नई गतिविधियां जुड़ती हैं, तो उन्हें जीडीपी में सही ढंग से शामिल करने के लिए उसके तरीके अपडेट करने पड़ते हैं। फरवरी महीने की शुरुआत में इन्फ्लेशन बास्केट में बदलाव किया गया और उसके बाद, अब 2022-23 को नया बेस ईयर मानकर जीडीपी के गणित को फिर से बनाया जा रहा है और 27 फरवरी से पिछले कुछ सालों के बैक-सीरीज़ डेटा भी जारी किए गए हैं। फरवरी महीने की शुरुआत में, सरकार ने जनवरी के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आधारित इन्फ्लेशन डेटा जारी किया, जो बेस ईयर 2024 के साथ नई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीरीज के तहत पहली रीडिंग था। यह भी बताया जा रहा है कि यह कवायद एक्यूरेसी को बेहतर बनाने के मकसद से इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स के बड़े रिवीजन का एक हिस्सा है, जिसमें ज़्यादा ग्रेन्युलर इंडिकेटर्स शामिल होंगे जो कोरोना महामारी के बाद खपत में आये बदलाव और डिजिटल इकॉनमी के तेजी से विस्तार को बेहतर ढंग से कैप्चर करेंगे और अर्थव्यवस्था की हालत बेहतर तरीके से समझी जा सकेगी।

मिनिस्ट्री ऑफ़ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का कहना है कि यह परिवर्तन/संशोधन मौजूदा खर्च के पैटर्न को बेहतर ढंग से दिखाने और उसकी शुद्धता में सुधार करने के लिए लागू किया जा रहा है। इसके तहत नवीनतम घरेलू खपत सर्वे और ताजा मार्केट डेटा का इस्तेमाल करके इन्फ्लेशन बास्केट को अपडेट किया जा रहा है। इंडस्ट्रियल आउटपुट में बदलाव का एक मुख्य माप इंडेक्स ऑफ़ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सीरीज़ होती है उसे बेस ईयर 2022-23 वाली बनाया जा रहा है। नई सीरीज 28 मई, 2026 को जारी होने वाली है। उसे भी डेटा को अपडेट करने और इसे बदले हुए नेशनल अकाउंट्स फ्रेमवर्क के साथ अलाइन रखने की कोशिशों का हिस्सा बताया जा रहा है। इसीलिए डिजिटल सर्विस और रिन्यूएबल एनर्जी जैसी नई इंडस्ट्री, कंजम्पशन में बदलाव और इन्वेस्टमेंट पैटर्न में बदलाव को शामिल करने के लिए बेस ईयर को 2011-12 से 2022-23 में अपडेट किया जा रहा है। इसके अलावा भी सभी सेक्टरों में मेंप के तरीकों को सुधारा जा रहा है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस क्षेत्रों में अब कीमतों में बदलाव के असर को बताने के लिए जीडीपी की नई गणित में नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जायेगा जिनसे अनौपचारिक (इनफॉर्मल) और गिग इकॉनमी के हालात को सर्वे, जीएसटी डेटा और दूसरे हाई-फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर का इस्तेमाल करके बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया जा सकेगा। नई व्यवस्था में तिमाही जीडीपी अनुमानों को एक नए बेंचमार्किंग तरीके -प्रोपोर्शनल डेंटन तरीके- के जरिये बेहतर बनाया जाएगा। शॉर्ट-टर्म इकॉनमिक ट्रेंड को उनकी संपूर्णता में दिखाने के लिये बिना किसी बनावटी उछाल के तिमाही नंबरों को सालाना कुल के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे यह संपूर्णता सुनिश्चित होगी। इसके अलावा, फूड सब्सिडी, जिसे पहले प्रोडक्ट सब्सिडी में गिना जाता था, अब ट्रांसफर इन काइंड के तौर पर माना जायेगा। नई सीरीज में ग्रॉस जीएसटी और कम्पनसेशन सेस के बजाय सेस समेत नेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कलेक्शन का इस्तेमाल किया जायेगा, जबकि स्टेट एक्साइज, यूनियन एक्साइज, सेल्स टैक्स और कस्टम्स ड्यूटी को उनकी असल वैल्यू का इस्तेमाल करके दिखाया जाएगा।

सवाल उठता है कि बेस ईयर को अभी क्यों अपडेट किया जा रहा है, और इसे कितनी बार बदला जाएगा? अधिकृत तौर पर बताया गया है कि यह बदलाव पहले ही अपेक्षित था। पिछले कुछ समय में देश की अर्थव्यवस्था में कुछ दूरगामी इकॉनमिक बदलाव हुए हैं। पहले जीएसटी आया, और फिर कोविड आ गया। अर्थव्यवस्था को दर्शाने वाले आंकड़ों को अपडेट करने की आवश्यकता इसलिये भी बनी क्योंकि पिछले साल इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड (आइएमएफ) ने भारत के नेशनल अकाउंट्स स्टैटिस्टिक्स के लिए मेथड की कमियों को इंगित किया था और इसे सी रेटिंग दी थी। इसका मतलब था कि आईएमएफ को सरकार ने जो डेटा दिए थे उनमें कुछ कमियां थी जो, कुछ हद तक आकड़ों पर नजर रखने में रुकावट डालती थीं। बताया गया है कि यह बदलाव अब किया जा रहा है क्योंकि भारत की इकोनॉमी के बदलते स्ट्रक्चर को बेहतर ढंग से दिखाने के लिए ज़्यादा अपडेटेड और भरोसेमंद डेटा उपलब्ध है। उम्मीद की जा रही है कि भविष्य में बेस ईयर में बदलाव हर पांच साल में या उसके आसपास किया जाएगा। पहले जीडीपी के अनुमान सर्वे और सीमित डेटा पर आधारित होते थे। अब डिजिटल रजिस्ट्रेशन, जीएसटी डेटा, कंपनी मामलों के मंत्रालय के रिकॉर्ड जैसे स्त्रोतों से अधिक सटीक आंकड़े मिलने लगे हैं जिनका उपयोग करके जीडीपी का चित्र अधिक स्पष्ट बनाया जा सकता है। जीडीपी मापने के लिए संयुक्त राष्ट्र की सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स गाइडलाइन भी होती है। भारत सरकार समय-समय पर इन मानकों के अनुसार अपने तरीकों को अपडेट करती रहती है ताकि उनकी वैश्विक तुलना आसान और भरोसेमंद हो। इसीलिए इसमें नवीनतम घरेलू खपत एवं एक्सपेंडिचर सर्वे, अनइनकॉरपोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइजेज का सालाना सर्वे, लेबर फोर्स का आवधिक सर्वे, उद्योगों का वार्षिक सर्वे और ऑल-इंडिया डेट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे शामिल हैं, जो मिलकर खपत, रोज़गार और बिजनेस एक्टिविटी की ज़्यादा माक़ूल तस्वीर प्रस्तुर करते हैं। इसके अलावा, सरकार कवरेज और एक्यूरेसी को बेहतर बनाने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स डेटा, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, ई-वाहन गाड़ी रजिस्ट्रेशन डेटा और पेट्रोलियम सेक्टर डेटा जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा सोर्स का प्रमुखता से इस्तेमाल कर रही है, जिससे यह पक्का करने में मदद मिलेगी कि नेशनल अकाउंट्स अलग-अलग सेक्टर्स में स्ट्रक्चरल बदलावों को बेहतर ढंग से पकड़ सकें।

भारत की अर्थव्यवस्था पहले कृषि-प्रधान थी, लेकिन अब सेवाक्षेत्र, आईटी, बैंकिंग, स्टार्टअप, डिजिटल सेवाएं आदि का योगदान बहुत बढ़ गया है। जब अर्थव्यवस्था में नई-नई गतिविधियां जुड़ती हैं, तो उन्हें जीडीपी में सही ढंग से शामिल करने के लिए उसके तरीके अपडेट करने पड़ते हैं। फरवरी महीने की शुरुआत में इन्फ्लेशन बास्केट में बदलाव किया गया और उसके बाद, अब 2022-23 को नया बेस ईयर मानकर जीडीपी के गणित को फिर से बनाया जा रहा है और 27 फरवरी से पिछले कुछ सालों के बैक-सीरीज़ डेटा भी जारी किए गए हैं।

इस बड़े बदलाव का मुख्य मकसद डबल डिफ्लेशन की ओर बदलाव भी है। यह एक ऐसा तरीका है जो रियल वैल्यू एडेड को ज़्यादा सही तरीके से मापने के लिए इनपुट और आउटपुट की कीमतों को अलग-अलग एडजस्ट करता है। इससे अनुमानों में सुधार होने की उम्मीद है, खासकर मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में, जहां इनपुट और आउटपुट की कीमतों के बीच अंतर ने पहले के सिस्टम की गड़बड़ियों के बारे में चिंताएं पैदा की थीं। इन बदलावों से गिग और डिजिटल इकॉनमी को भी बेहतर ढंग से कैप्चर किया जाने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि गिग वर्क पहले से ही जीडीपी अनुमानों में शामिल था, लेकिन अब इसे इंडिकेटर्स की एक बड़ी रेंज, जिसमें अनइनकॉरपोरेटेड एंटरप्राइजेज के सर्वे, कॉर्पोरेट फाइलिंग और जीएसटी डेटा शामिल हैं, का इस्तेमाल करके ज़्यादा सही तरीके से दिखाया जा सकेगा। इससे यह पक्का होगा कि प्लेटफॉर्म-बेस्ड और सेल्फ-एम्प्लॉयड वर्कर्स और बेहतर तरीके से दर्ज हो सकें। इसी तरह, इनफॉर्मल सेक्टर को और गहराई से मापाने की ओर कदम बढ़ाया गया है। इस माप के लिये डेटा की कमी को पूरा करने के वास्ते रोज़गार के पैटर्न और घरेलू कामों को ट्रैक करने वाले सर्वे के साथ-साथ मोटर गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और फ्यूल की खपत जैसे हाई-फ्रीक्वेंसी डेटा का भी इस्तेमाल किया जाने लगा है। इन बदलावों का मकसद फ़ॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों क्षेत्रों को साथ मिलाकर आर्थिक गतिविधियों की ज़्यादा पूरी और असली तस्वीर प्रस्तुत करना बताया गया है।

अर्थशास्त्रियों का कहना है कि बदली हुई सीरीज़ भारत के महंगाई और जीडीपी डेटा मौजूदा अर्थव्यवस्था को ज़्यादा ऊंची दिखाएगी। निवेशकों और बाज़ार भारत की महंगाई और उसके नेशनल अकाउंट का सही आकलन कर पाएंगे और वे अर्थव्यवस्था की असली ऊंचाई को देख पाएंगे, क्योंकि महंगाई और जीडीपी दोनों के नंबर मौजूदा खपत और प्रोडक्शन पैटर्न को दिखाएंगे। नई व्यवस्था में सेवा क्षेत्र (सर्विसेज़) का वज़न ज़्यादा होने की संभावना है और आम तौर पर खेती की तुलना में वहां तेज़ी से वृद्धि होगी। नई सीरीज़ ज़्यादा औसत असली जीडीपी ग्रोथ दिखा सकती है, भले ही असल अर्थव्यवस्था वही रहे। वर्ष 2024-2026 की नई जीडीपी सीरीज देश की अर्थव्यवस्था के आकार और तिमाही ग्रोथ रेट को बदल सकती है। ये डेटा पॉइंट्स भारत के ग्रोथ-इन्फ्लेशन मिक्स और मॉनेटरी पॉलिसी एक्शन की दिशा का फिर से आकलन करने के लिए अहम हो सकते हैं।

जीडीपी की गणना में एक आधार वर्ष तय किया जाता है, जिससे कीमतों की तुलना की जाती है। केंद्र सरकार ने समय-समय पर -1993-94, 1999-2000, 2004-05 और 2011-12 में बेस ईयर बदला है। अब सरकार नई आर्थिक वास्तविकताओं को शामिल करने के लिये 2022-23 को नया बेस ईयर बनाने पर काम कर रही है। अर्थशास्त्री कहते हैं कि बेस ईयर बदलने से जीडीपी में महंगाई का असर सही दिखेगा और उसमें नई कंपनियां और सेक्टर शामिल होंगे। मगर 2015 में जब नई सीरीज़ (2011-12 बेस ईयर) लागू हुई थी, तब कई अर्थशास्त्रियों की इस पद्धति पर बहस हुई थी। अंततः यह माना गया कि इसमें समय-समय पर समीक्षा और सुधार आवश्यक है। ऐसे सुधारों के समर्थक कहते हैं कि जीडीपी मापने के तरीके में बदलाव का उद्देश्य आंकड़ों को 'बढ़ाना' नहीं, बल्कि उन्हें अधिक सटीक, पारदर्शी और आधुनिक अर्थव्यवस्था के अनुरूप बनाना है। यद्यपि आधार वर्ष परिवर्तन और पद्धति सुधार एक सामान्य एवं आवश्यक प्रक्रिया है, ताकि वह पारदर्शिता, विश्वसनीयता और असंगठित क्षेत्र के समुचित आकलन को सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही सरकार को सांख्यिकीय प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाकर सभी पक्षों का विश्वास अर्जित करना चाहिए।

-अतिथि संपादक,
राजेन्द्र बोड़ा
(वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक)

राजस्थान का बदलता स्टार्टअप परिदृश्य और युवा सशक्तिकरण

के.के. विश्नोई

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राज्य ने स्टार्टअप, नवाचार और कौशल-आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में कदम बढ़ाकर विकास की पारंपरिक धारणाओं को नया आयाम दिया है। पिछले दिनों आयोजित राजस्थान स्टार्टअप समिट 2026 ने इस परिवर्तनशील परिदृश्य को एक मंच पर प्रस्तुत अवश्य किया। यह परिवर्तन दीर्घकालिक नीतिगत दृष्टि और प्रशासनिक इच्छाशक्ति का प्रतिफल है।

राजस्थान लंबे समय तक खनिज, हस्तशिल्प, कृषि और पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था के लिए जाना जाता रहा। डिजिटल क्रांति और नई अर्थव्यवस्था के दौर में राज्य ने स्वयं को तकनीकी उद्यिमता के अनुकूल ढालने का प्रयास किया है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा जैसे शहरों में अब फिनटेक, एग्रीटेक, हेल्थटेक और एडटेक स्टार्टअप्स का उभार स्पष्ट दिखाई देता है। विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों से निकलने वाली नई पीढ़ी पारंपरिक नौकरी की अपेक्षा उद्यमिता की ओर अग्रसर हो रही है।

राज्य सरकार की आई-स्टार्ट पहल के अंतर्गत 3450 से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत होना इस बात का प्रमाण है कि राजस्थान में उद्यिमता की संस्कृति विकसित हो रही है। प्रदेश के 658 स्टार्टअप्स को लगभग 22.5 करोड़ रुपये की कराई गई फंडिंग शुरुआती स्तर पर पूंजी की समस्या से जूझ रहे युवाओं के लिए संबल है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की यह पहल वित्तीय सहायता के साथ ही स्टार्टअप हब्स, टिंकरिंग लैब्स, डीप-टेक और एआई लैब्स की स्थापना की दिशा में बजटीय प्रावधान भविष्य की तकनीकों के प्रति राज्य की प्राथमिकता का प्रमाण है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट सम्मिट 2024 में 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू हस्ताक्षिरत होना और 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक निवेश पर कार्य प्रारंभ होना यह संकेत देता है कि राजस्थान निवेशकों की रुचि में मजबूती से स्थापित हो चुका है। निवेश का यह प्रवाह यदि स्टार्टअप इकोसिस्टम से जुड़ता है, तो बड़े उद्योगों और नवाचार आधारित उद्यमों के बीच सहजीवी संबंध स्थापित हो सकते हैं। सेमीकंडक्टर और एयरोस्पेस जैसी नीतियां उच्च-तकनीकी विनिर्माण के लिए मार्ग प्रशस्त करने से तकनीकी कौशल की मांग और स्टार्टअप अवसर दोनों बढ़ेंगे। राजनिवेश पोर्टल और सिंगल विंडो क्लीयरेंस प्रणाली के माध्यम से 2 हजार से अधिक प्रस्तावों को स्वीकृति दी जा चुकी है। इनका प्रस्तावित निवेश लगभग 49 हजार करोड़ रुपये है।

स्टार्टअप्स के लिए समय और प्रक्रिया की लागत सबसे बड़ी चुनौती होती है। भूमि उपयोग परिवर्तन में सरलीकरण और औद्योगिक क्षेत्रों में अनावश्यक एनओसी समाप्त करना उद्यमिता के मार्ग की बाधाओं को कम करना महत्वपूर्ण सुधार सकारात्मक संकेत हैं।

राजस्थान एमएसएमई नीति-2024 के अंतर्गत 3,410 उद्योगों को प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। स्टार्टअप और एमएसएमई के बीच सहयोग की संभावनाएं विशाल हैं। पारंपरिक उद्योग नवाचार आधारित समाधान जैसे एग्रीटेक के माध्यम से कृषि आपूर्ति श्रृंखला में सुधार या डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हस्तशिल्प के वैश्विक विपणन आदि अपनाकर रोजगार और आय दोनों में वृद्धि कर सकते हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का प्रयास है कि युवा केवल रोजगार मांगने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला बने। राजस्थान युवा नीति और रोजगार नीति इसी दृष्टि को आगे बढ़ाती हैं। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के माध्यम से 18 से 45 वर्ष तक के युवाओं को ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराना उद्यमिता को प्रोत्साहन देता है। प्रदेश के 33 जिलों में 65 लॉन्च पैड विकसित कर सरकार ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों तक स्टार्टअप संस्कृति पहुंचाने का प्रयास कर रही है। राजस्थान ने एनीमेशन, गेमिंग, एक्सटेंडेड रियलिटी और कॉमिक्स जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यह संकेत है कि राज्य पारंपरिक उद्योगों से आगे बढ़कर रचनात्मक अर्थव्यवस्था को भी महत्व दे रहा है। युवा आबादी और डिजिटल पहुंच को देखते हुए यह क्षेत्र रोजगार के नए अवसर सृजित कर सकते हैं।

राजस्थान का वर्तमान स्टार्टअप परिदृश्य संक्रमण काल में है। यहां नीतियां आकार ले चुकी हैं, निवेश प्रवाहित हो रहा है और युवा तैयार हैं। अब आवश्यकता है क्रियान्वयन की निरंतरता और पारदर्शिता की। राज्य सरकार की पहलें, निजी निवेश और युवाओं की नवाचारी ऊर्जा से राजस्थान आने वाले वर्षों में स्टार्टअप और कौशल-आधारित अर्थव्यवस्था का मजबूत मॉडल बन रहा है। राजस्थान भविष्य गढ़ने की तैयारी में है और इस भविष्य की धुरी नवाचार, कौशल और युवा उद्यमिता है।

-के.के. विश्नोई,
उद्योग, युवा मामले, कौशल,
नियोजन एवं उद्यिमता राज्य मंत्री

मेवाड़-वागड़ क्षेत्र की उपेक्षा

डॉ. पी. सी. कंठालिया

राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरण तब आया जब 'राजस्थान संघ में उदयपुर रियासत का विलय हुआ और इसका नया नाम 'संयुक्त राजस्थान रखा गया। उदयपुर के शासक महाराणा भूपालसिंह मेवाड़ की 20 लाख जनता की इच्छा के अनुरूप विलय के लिए सहमति जाहिर की 23 मार्च 1948 को महाराणा ने प्रधानमंत्री सर राममूर्ति को दिल्ली भेजा और तत्कालीन गृहमंत्री सरदार पटेल के अधीन एकीकरण का काम देख रहे वीपी मेनन के पास गए उन्होंने अपनी मांगें भारत सरकार के सामने रखीं इस दौरान एक मांग थी उदयपुर को संयुक्त राजस्थान की राजधानी बनाया जाए 18 अप्रैल, 1948 को स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में, उदयपुर के फतेह प्रकाश पैलेस के दरबार हॉल में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए, तभी राजस्थान संघ का नाम बदलकर 'संयुक्त राजस्थान कर दिया गया महाराणा भूपालसिंह को राजप्रमुख और प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया मेवाड़ के शामिल होने के साथ ही उदयपुर को राजधानी शहर भी बनाया गया।

14 जनवरी, 1949 को सरदार वल्लभभाई पटेल भी उदयपुर आए दो माह बाद 30 मार्च 1949 को मेवाड़ के नेतृत्व में अन्य बड़ी रियासतों द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद राजस्थान का नया राज्य बना इसके बाद राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थानांतरित कर दी गई और जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह को राजस्थान का राज-प्रमुख नियुक्त किया गया। वहीं, महाराणा भूपाल सिंह को आजीवन महाराज-प्रमुख के पद पर पदोन्नत किया गया इसी के चलते 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाने की परंपरा की शुरू हुई इस तरह राजस्थान राज्य के गठन में मेवाड़ महाराणा भूपालसिंह की प्रमुख भूमिका रही परन्तु आज यही मेवाड़ - वागड़ क्षेत्र उपेक्षा का शिकार है।

मेवाड़ का इतिहास केवल राजस्थान का नहीं, बल्कि संपूर्ण भारत के शौर्य और स्वाभिमान का प्रतीक है। मेवाड़, राजस्थान का एक ऐसा क्षेत्र है जिसने स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए सदियों से संघर्ष किया है। मेवाड़ के राजाओं ने शपथ ली थी कि जब तक दिल्ली पर विदेशियों का शासन रहेगा, वो दिल्ली नहीं जाएंगे। लेकिन आज 2026 के परिप्रेक्ष्य में जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तो गौरवशाली अतीत के बावजूद मेवाड़ की उपेक्षा का प्रश्न बार-बार खड़ा होता है। मेवाड़-वागड़ क्षेत्र, जो राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित है, पिछले कई दशकों से उपेक्षा का शिकार हो रहा है। यह क्षेत्र अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इसके बावजूद, यहां के लोगों को विकास और सुविधाओं के मामले में बहुत पीछे छोड़ दिया गया है।

मेवाड़-वागड़के साथ हमेशा अन्याय हुआ है चाहे कांग्रेस सरकार हो या बीजेपी सरकार उदयपुर के लिए लगभग स्वीकृत आई.आई.टी. कोटा होकर जोधपुर चली गयी। सबसे अधिक झीले उदयपुर में है परन्तु झील प्राधिकरण का मुख्यालय जयपुर को दिया गया, सबसे अधिक वन क्षेत्र उदयपुर संभाग में है परन्तु वन अनुसन्धान संस्थान जोधपुर में है। राजस्थान में मेवाड़ को छोड़कर जोधपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर, जयपुर संभाग में 30 साल पूर्व ही रल्वे ब्रॉड गेज जोड़ दिया गया था, इन शहरों से देश के हर कोने के लिए रेलवे सुविधा है। इधर आज हम उदयपुर - अहमदाबाद - मुंबई, उदयपुर -मारवाड़ रेलवे के ब्रॉड गेज के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बांसवाडा - रतलाम रेल लाइन फाइलों में दब गई है, कोई सुनने वाला नहीं। आदिवासी क्षेत्र में रेलवे के लिए मात्र आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला है। उदयपुर स्थित खान एवं भूविज्ञान विभाग एवं एस.आई.आर.टी. आदि को कमजोर कर जयपुर ले जाने की तैयारी की जा रही है।

मध्य प्रदेश के विभाजन के बाद क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसकी विशालता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि बांसवाड़ा से श्री गंगानगर की यात्रा में लगभग 24 घंटे का समय लग जाता है। इतने बड़े राज्य को एक ही प्रशासन के तहत चलाना एक बड़ी चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि छोटे राज्य के गठन से तेजी से विकास होता है, इसी कारण उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ एवं झारखण्ड को पृथक राज्य बनाने के लिए जोर-शोर समर्थन दिया था मेवाड़- वागड़ क्षेत्र के भी कई लोगों का मानना है कि राजस्थान को छोटे-छोटे राज्यों में बांटा जाये ताकि इस क्षेत्र का तेजी से विकास हो। उदयपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ स्थापित करने की मांग पिछले कई दशकों से की जा रही है। उदयपुर में उच्च न्यायालय की पीठ स्थापित करने की मांग 1970 के दशक से की जा रही है। 1980 के दशक में इस मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने हड़ताल की थी। 2013 में मेवाड़-वागड़ हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति ने इस मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया था। उदयपुर राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित है, जो जोधपुर से काफी दूर है। यहां के लोगों को न्याय पाने के लिए जोधपुर जाना पड़ता है, जो समय और पैसा दोनों की बर्बादी है। उदयपुर में उच्च न्यायालय की पीठ स्थापित करने की मांग को लेकर आंदोलन जारी है परन्तु इतने लम्बे संघर्ष के बावजूद कोई सफलता नहीं मिली है। राजस्थान में कृषि विकास को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से वर्ष 1987 में बीकानेर में एक स्वतंत्र कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। राज्य की विशाल भौगोलिक विविधता, विभिन्न फसल पद्धतियों, जलवायु परिस्थितियों एवं मृदा मानकों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1999 में राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों का पुनर्गठन किया गया, जिसके अंतर्गत महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का गठन हुआ। दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज यही विश्वविद्यालय सरकार की घोर उपेक्षा का शिकार बना हुआ है। विश्वविद्यालय में लगभग 80 प्रतिशत अध्यापकों एवं कृषि वैज्ञानिकों के पद वर्षों से रिक्त पड़े हैं, जिससे न केवल शिक्षा और शोध प्रभावित हो रहा है, बल्कि राज्य के कृषि विकास की गति भी अवरुद्ध हो गई है। स्थिति यहाँ तक गंभीर हो चुकी है कि विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनकी वैध पेंशन तक समय पर नहीं मिल पा रही है। कम्प्यूटेड पेंशन का भुगतान पूर्णतः बंद कर दिया गया है तथा ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए कर्मचारियों को दो-तीन वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ रही है। यह न केवल प्रशासनिक विफलता को दर्शाता है, बल्कि उन कर्मचारियों के प्रति घोर अन्याय भी है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस संस्थान की सेवा में समर्पित कर दिया।

मेवाड़-वागड़ राज्य का गठन एक ऐसा विचार है जो कई वर्षों से चर्चा में है। यह क्षेत्र वर्तमान राजस्थान राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित है, जिसमें उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, और राजसमंद जिले शामिल हैं। मेवाड़-वागड़ की भौगोलिक स्थिति राजस्थान के अन्य क्षेत्रों से काफी अलग है। यह क्षेत्र अरावली पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जो इसे एक अलग भौगोलिक इकाई बनाता है। यहां की जलवायु भी राजस्थान के अन्य भागों से अलग है, जो अधिक आर्द्र और शीतल है। जलवायु एवं फसल चक्र के अतिरिक्त रीति रिवाज एवं समस्याओं में भी विभिन्नता है।

मेवाड़-वागड़ क्षेत्र की उपेक्षा एक चिंताजनक स्थिति है, मेवाड़-वागड़ क्षेत्र की उपेक्षा के कई कारण हैं।

मेवाड़-वागड़ क्षेत्र को राजनीतिक रूप से अनदेखा किया गया है, जिससे यहां के लोगों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ता है।उदयपुर में लम्बे संघर्ष के बावजूद भी रजस्थान उच्च न्यायालय के पीठ की स्थापना नहीं हो पाई और बीकानेर को यह पीठ दे दी गई, चुनाव के बाद यहाँ से विजयी राजनेता मेवाड़-वागड़ क्षेत्र को भूल जाते हैं

राजस्थान के दक्षिणी भाग के आदिवासियों के लिए 7.5 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, यहाँ के आदिवासी मीना कहलाते है परन्तु इसका लाभ पूर्णतया नहीं मिला। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग ने 'भील मीना' के लिए आरक्षण की सिफारिश की थी। लेकिन एक छपाई की गलती (भील और मीना के बीच अल्पविराम) के कारण पूरे मीना / मीणा समुदाय को आरक्षण मिल गया। आज तक कोई भी भील मीना आईएस अधिकारी नहीं बना। आरक्षण का लाभ जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर और करौली जिला के मीणा भी उठा रहे हैं क्योंकि छपाई की गलती से इन्हें अनुसूचित जनजाती में मान लिया गया यह आरक्षण केवल राजस्थान में है।

इस क्षेत्र में विकास की कमी है, जिससे यहां के लोगों को बुनियादी सुविधाओं के लिए तरसना पड़ता है। मेवाड़-वागड़ क्षेत्र में भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है, जिससे विकास कार्यों में बाधा आती है। मेवाड़-वागड़ क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिससे यहां के लोगों को नुकसान हो रहा है। आज हम अरावली पर्वत को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं

मेवाड़-वागड़ क्षेत्र की उपेक्षा के परिणाम बहुत गंभीर देखने को मिल रहे हैं। इस क्षेत्र में गरीबी एक बड़ी समस्या है, जिससे लोगों को अपने परिवार का पालन-पोषण करने में कठिनाई हो रही है। रोजगार नहीं मिलाने के कारण लोगो का पलायन हो रहा है। मेवाड़-वागड़ क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं की कमी है, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली आदि। मेवाड़-वागड़ क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों का नुकसान हो रहा है, जिससे यहां के लोग को प्रभावित हो रहे हैं।

मेवाड़-वागड़ राज्य की स्थापना से कई आर्थिक लाभ हो सकते हैं। एक अलग राज्य बनने से प्रशासनिक कार्य अधिक प्रभावी ढंग से चलाए जा सकते हैं, और लोगों को अपने अधिकारों का अधिक आसानी से उपयोग करने का अवसर मिल सकता है। एक अलग राज्य बनने से मेवाड़-वागड़ क्षेत्र में राजस्व में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि राज्य सरकार को अधिक अधिकार मिलेंगे और वे अपने संसाधनों का बेहतर उपयोग कर सकेंगे। एक अनुमान के अनुसार राजस्थान के राजस्व में मेवाड़-वागड़ क्षेत्र का योगदान लगभग 47 प्रतिशत है। मेवाड़-वागड़ क्षेत्र में उद्योगों का विकास हो सकता है, क्योंकि राज्य सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नीतियों और योजनाओं को लागू कर सकती है। सीमेंट के लिए आवश्यक खनिज प्रदार्थ के बहुतायत से उपलब्ध है इस कारण कई सीमेंट उद्योग की स्थापना हो सकती है।

मेवाड़-वागड़ क्षेत्र में पर्यटन में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि राज्य सरकार पर्यटन स्थलों को विकसित करने और प्रचार करने पर ध्यान केंद्रित कर सकती है। मेवाड़-वागड़ क्षेत्र में कृषि विकास हो सकता है, क्योंकि राज्य सरकार कृषि को बढ़ावा देने के लिए नीतियों और योजनाओं को लागू कर सकती है। जैविक खेती को बढ़ावा मिल सकता है।

मेवाड़-वागड़ राज्य की स्थापना से रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं, क्योंकि उद्योगों और सेवाओं का विकास होगा। मेवाड़-वागड़ राज्य की स्थापना से बुनियादी ढांचे का विकास हो सकता है, जैसे कि सड़कें, पुल, बिजली, पानी आदि।

मेवाड़-वागड़ राज्य की स्थापना से राज्य के संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकता है, जैसे कि खनिज, वन, जल आदि। वागड़- मेवाड़ क्षेत्र विशेष रूप से उदयपुर, बांसवाड़ा और राजसमंद जैसे जिले, खनिजों से समृद्ध हैं, जिनमें सीसा, जस्ता, चांदी और मैंगनीज प्रमुख हैं। इनके अलावा, यहाँ तांबा, लौह अयस्क, संगमरमर, ग्रेनाइट और विभिन्न औद्योगिक खनिज जैसे बैराइट्स, फेल्डस्पार और चाइना क्ले के भी पर्याप्त भंडार हैं, जो अरावली पर्वतमाला की महत्वपूर्ण खनिज संपदा को दर्शाते हैं। प्रमुख स्थलों में सीसा-जस्ता के लिए जावर (उदयपुर) और मैंगनीज के लिए बांसवाड़ा शामिल हैं। वैज्ञानिक तौर से दोहन के लिए कई उद्योग का विकास हो सकता है

अतः कुशुल प्रशासन एवं न्यायोचित विकास के लिए अलग से मेवाड़ राज्य की स्थापना की मांग की जाये भारत में स्वतंत्रता के बाद कई राज्यों को विभाजित किया गया है। विभाजन के बाद तेजी से विकास किया है, अगर मेवाड़- वागड़ राज्य की मांग की जाय और मांग मान ली जाती है तो राजधानी उदयपुर बनने पर इस क्षेत्र की सारी मांगे स्वतः ही पूरी हो जाएगी। मेवाड़ का भी तेजी से विकास हो सकता है, मेवाड़-वागड़ राज्य की स्थापना से उच्च न्यायालय को स्थापित करने कोई नहीं रोक सकता है।

-डॉ. पी. सी. कंठालिया,
पूर्व प्रोफेसर एवं मुख्य मृदा वैज्ञानिक

राशिफल शुक्रवार 6 मार्च, 2026

पंडित अनिल शर्मा

चैत्र मास, कृष्ण पक्ष, तृतीया तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत 2082, हस्त नक्षत्र प्रातः 9:30 तक, गंड योग प्रातः 7:06 तक, विष्टि करण सायं 5:54 तक, चन्द्रमा आज रात्रि 10:19 से तुला राशि में संचार करेगा।

गृह स्थिति: सूर्य-कुम्भ, चन्द्रमा-कन्या, मंगल-कुम्भ, बुध-कुम्भ, गुरू-मिथुन, शुक्र-मीन, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह

आज राजयोग दिन 9:30 से सायं 5:54 तक है। भद्रा प्रातः 5:29 से सायं 5:54 तक रहेगी। आज कल्पादि, चतुरथी व्रत है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 8:17 तक, लाभ-अमृत 8:17 से 11:11 तक, शुभ 12:38 से 2:05 तक, चर 4:59 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 6:50, सूर्यास्त 6:26

मेष
परिवार में चल रहे आपसी मतभेद दूर होने लगेंगे। दिनचर्या में सुधार होगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे।

वृष
परिजनों के व्यवहार के कारण मन खिन्न हो सकता है। आपसी ईर्ष्या-वैमनस्यता के कारण परेशानी हो सकती है। आज व्यावसायिक/आर्थिक मामलों पर ध्यान देना अच्छा रहेगा।

मिथुन
घर-परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। धार्मिक-मांगलिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कर्क
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। मित्रों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

सिंह
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे।

कन्या
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक अड़चनें दूर होने लगेंगी। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

तुला
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण मानसिक तनाव बना रहेगा। व्यावसायिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

वृश्चिक
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संभावित धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में उचित सफलता मिलेगी।

धनु
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक अड़चनें दूर होने लगेंगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं।

मकर
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है।

कुंभ
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। यात्रा में परेशानी हो सकती है।

मीन
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।